सेवा कार्यक्रम जो समयवद्ध पद्धति से पूरे कवरेज के लिए पहचान किया गया है, को नौवी योजना में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

Know-how in Space Research to Middle-East Countries

1473. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any of the Middle-East Countries have approached Indian Space Research Organisation (ISRO) for providing technical know-how in the field of space research;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what are the steps taken by ISRO to capture the World Space Research market, especially in the third world countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Department of Space has set up a company — Antrix Corporation Limited, specifically for the marketing of Indian space products and services and Antrix has been actively pursuing the space market in the third world countries, through responding to tenders, undertaking publicity exercises, as well as inviting the concerned agencies for visits and discussions in India to apprise them of our capabilities. In this process, Antrix has already secured some contracts from a few developing countries.

Rayalty on Crude Oil and Natural Gas

1474. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the criteria for fixing the rate of royalty on crude oil and natural Gas;

(b) when the rate of royalty on crude oil was revised last, alongwith the rates thereof; and

(c) by when the rate of royalty is likely to be revised further;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Royalty on crude oil and natural gas in governed by the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(b) The rate of royalty on crude oil was last revised to Rs. 481 per metric tonne in February, 1993.

(c) The royalty will be revised after the well-head price w.e.f. 1993 is fixed.

Subsidy on Petroleum Products and oil Pool Account Deficit

1475. SHRI O.P. KOHLI Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether subsidy on petroleum products during the current financial year is going to cross Rs. 18,000 crores;

(b) whether the oil pool account deficit would reach unmanageable proportion at Rs. 15,500 crores and if so, the reasons therefor;

(c) whether the country is faced with rise in deficit in oil pool account, in spite of recent heavy increase effected in the prices of petroleum products, and

(d) how Government propose to tackle this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BALLU): (a) The subsidy on petroleum products during 1996-97 is estimated at Rs. 18,440 Crores.

(b) to (d) The cumulative outstandings of the oil companies from the oil pool account are estimated to rise to Rs. 15,500 crores by 31.3.97. Deficits have arisen in the pool account because the sales realisation from the products did not fully cover the costs incurred. The position of the oil pool account is monitered on a continuous basis and remedial measures taken to contain the deficit.

स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योग

1476. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को प्रदान की गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) उद्योग मंत्रालय स्व-रोजगार योजना जैसे 2 अक्तूबर, 1993 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना को क्रियान्वित कर रहा है। उनसे प्राप्त सामग्री के अनुसार 1993-94 के दौरान योजना केवल शहरी क्षेत्रों में तथा 1994-95 से अब तक समस्त देश में संचलित है। योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में लघु उद्यम स्थापित किए जाते हैं। इसके कार्यान्वयन में ग्रामीण व शहरी आधार पर विभिन्नता नहीं रखी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों में विभिन्नता को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ग्रामीण/शहरी आधार पर आंकड़ों को नहीं बना और नहीं रख रहे हैं। अतः ग्रामीण/शहरी आधार पर अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत लोगों की संख्या वितरित ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार है:—

क्र सं॰	वर्ष	संस्वीकृत लोग (संख्या)	लोग (वितरित ऋण) (संख्या)
1.	1993-94	32,116	22,734
2.	1994-95	1,98,224	1,41,521
3.	1995-96	2,99,118	1,78,260

(ख) भारत सरकार परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी देती है बशर्ते कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमों को स्थापित करने हेतु प्रति उद्यम की अधिकतम राशि 7,500 रुपए हो। योजना के तहत पूंजी सब्सिडी भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थियों को दिए गए ऋणों को समायोजित करने के लिए कार्यान्वित बैंकों को सब्सिडी सौंपती है। 1995-96 के दौरान पूंजी सब्सिडी के रूप में 120 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सम्मिलित है, के लिए स्व-रोजगार योजना के तहत 1.80 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, शामिल हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रेषित सब्सिडी को लाभार्थियों को दिए गए ऋणों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक-वार बनाया गया है। सब्सिडी आबंटन राज्यवार नहीं बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों को कवर करने के लिए 2.20 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। योजना चालू वर्ष के दौरान चल रही है।

Construction of Bridges over west Yamuna Canal

1477. SHRI K.M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether foundation stones for construction of new bridges over West Yamuna Canal connecting Pocket-U & V Shalimar Bagh and Pocket-KU, Pitampura, were laid in December, 1994 and about one lakh rupees were spent on stone laying ceremony;

(b) whether the above work was to be completed within 12 months from the date of stone laying, but the same could not be completed even after lapse of nearly two years; and